

रेलवे में नौकरी लगवाने का दावा कर हड़पे साढ़े सोलह लाख, केस दर्ज

लखनऊ लखनऊ में डीआरएफ ऑफिस में तैनात होने का दावा करने वाले ठग ने एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने का झांसा देकर साढ़े सोलह लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने आलमबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मानकनगर निवासी मुकेश तिवारी की पत्नी सपना तिवारी नौकरी की तलाश कर रही थी। इस सिलसिले में उनकी बात अशोक कुमार से हुई थी। जो पूर्व परिचित है। मुकेश के अनुसार अशोक ने भाई पवन कुमार अवस्थी के जरिए रेलवे में क्लर्क के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था। अशोक का दावा था कि पवन डीआरएफ ऑफिस में तैनात है। अधिकारियों में अच्छी पैठ होने के कारण वह पहले भी कई लोगों को नौकरी दिला चुका है। पूर्व परिचित पर विश्वास कर सपना उनके झांसे में फंस गई थी। साथ ही नौकरी लगवाने में खर्च के तौर पर 16 लाख 70 हजार रुपये चेक के जरिए दिए थे। मुकेश के मुताबिक रुपये लेने के बाद पवन का व्यवहार बदल गया।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

मुख्य संवाददाता : इन्द्रजीत सिंह मो. 9582093548

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 21 ● अंक: 144 ● नई दिल्ली

● मंगलवार 18 जनवरी 2022 ● प्रभात कालीन

● मूल्य: 3 रूपया

● पृष्ठ: 8

कड़ाके की ठंड जारी

दिल्ली में लगातार सर्द दिन का रिकॉर्ड

नई दिल्ली । मैदानी इलाकों में जारी कड़ाके की ठंड का दौर रविवार को भी जारी रहा। दिन के लुढ़के पारे की वजह से राजधानी में लगातार चौथे दिन सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन दर्ज होने की संभावना जताई है। साथ ही बच्चों व बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणि के मुताबिक, गत 13 जनवरी से शुरू हुआ अंडर टेंड दिन का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इस कड़ी में दिल्ली के कुछ इलाकों में लगातार चौथे दिन सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग



पर इस तरह की स्थिति नहीं रही। जेनामणि के मुताबिक, लगातार कोहरा और बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व

राजस्थान के कुछ हिस्सों में गंभीर स्तर की ठंड से लेकर ठंडा दिन रिकॉर्ड किया जा सकता है। रविवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिक कोहरा दर्ज किया गया। हालांकि, दोपहर 12 बजे के बाद सूरज निकला लोगों को हल्की धूप से थोड़ी बहुत राहत मिली। दिनभर

■ मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से आगामी 21 और 22 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इस कड़ी में 22 जनवरी के लिए विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया हुआ है।

रुक-रुककर धूप निकलने का सिलसिला जारी रहा। शाम होते ही लोग हीटर व अलाव से ठंड से बचने की कोशिश करते रहे। बीते 24 घंटे में दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन कम 17.2 व न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 62 से 92 फीसदी रहा। इस वजह से सुबह सड़कों पर मध्यम स्तर तक का कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में

अधिकतम तापमान 16 व न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से आगामी 21 और 22 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इस कड़ी में 22 जनवरी के लिए विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और यह 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है।



नयी दिल्ली। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इसने वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई को बेहद मजबूत बनाया और इसके चलते ही लोगों की जान बचाई जा सकी तथा सुरक्षित तरीके से आजीविका चलाई जा सकी। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक महामारी पहली बार आई थी, तब वायरस के बारे में ज्यादा नहीं पता था। हालांकि, हमारे वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों ने टीकों को विकसित करने में खुद को झोंक दिया। मोदी ने ट्वीट किया, “भारत को इस बात पर गर्व है कि हमारे देश ने टीकों के माध्यम से वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने में योगदान दिया।” उन्होंने कहा, मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूँ। हमारे चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका असाधारण रही है।”

टीकाकरण के सफलतम एक साल

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत का रुख हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान ने रविवार को एक साल पूरा कर लिया। इस दौरान टीके की 156.76 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, 92 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी को कम से कम एक खुराक दे दी गई है, जबकि 68 प्रतिशत से अधिक का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। टीकाकरण अभियान के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र आज डक टिकट जारी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने पिछले साल एक अप्रैल को टीके की 10 करोड़ खुराक देने की उपलब्धि हासिल कर ली थी। उन्होंने कहा कि 25 जून को 25 करोड़ खुराक, छह अगस्त को 50 करोड़ और 13 सितंबर को 75 करोड़ खुराकें देने का आंकड़ा पार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भारत के कोविड टीकाकरण अभियान के एक वर्ष के सफल समापन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि देश ने दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे सरकार और लोग मिलकर असंभव चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शाह ने इस प्रयास के लिए वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों, कोविड योद्धाओं और देश की जनता को बधाई भी दी।

पंजाब में मतदान टालने की मांग तेज: भाजपा और कैप्टन ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र, 16 फरवरी को गुरु श्री रविदास जयंती का दिया हवाला

चंडीगढ़ । पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने की मांग अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रविवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान टालने की मांग की है। इसके पीछे वजह 16 फरवरी को होने वाली संत गुरु श्री रविदास की जयंती बताई है। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और बहुजन समाज पार्टी की पंजाब इकाई यह मांग चुनाव आयोग से कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुबे में 14 फरवरी को होने वाली मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। भाजपा ने पत्र में लिखा है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का पावन पर्व होने के कारण राज्य का एक बड़ा वर्ग वाराणसी जा सकता है। ऐसे में यदि राज्य में मतदान हुआ तो वह लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह



जाएंगे। ऐसे में भाजपा पंजाब चुनाव आयोग से राज्य में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिन आगे बढ़ाने की मांग करती है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र की पुष्टि करते हुए पंजाब भाजपा के प्रदेश महासचिव डॉ. सुभाष शर्मा ने बताया कि भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनकी इस मांग पर गौर करेगा। भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए

वह नहीं चाहती कि कोई भी वर्ग अपने वोट के अहम अधिकार से वंचित रहे। वहीं, दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान प्रक्रिया की तिथि 20 फरवरी करने की मांग की है। भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय चंडीगढ़ में प्रकाशवाता में बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली के

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनने के लिए बनाया गया एए एक नाटक है। यह पूरी कवायद भगवंत मान को कुचलने की कुटिल चाल है। इसकी असली सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। जिसके बाद मान और केजरीवाल के बीच का बुलबुला फूट जाएगा। अब केजरीवाल शैली की राजनीति का नाटक चरम पर पहुंच गया है। अश्वनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पंजाब और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। दुर्भाग्य से आप के केंद्रीय नेता पंजाबी संस्कृति की बारिकियों, पंजाब के समृद्ध इतिहास के गौरव को नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर पाएंगे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है।

बगावत पर उतरे पंजाब सीएम चन्नी के भाई, कांग्रेस ने टिकट से किया इनकार अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

चंडीगढ़ । पंजाब विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम का वक बचा है लेकिन सत्ताधारी पंजाब कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिद्धू के साथ जारी सियासी उठापटक के बीच अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई बगावत पर उतर आए हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के छोटे भाई, डॉ मनोहर सिंह ने घोषणा की है कि वह बस्सी पठान निर्वाचन क्षेत्र से बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में चन्नी के भाई का नाम नहीं था। माना जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा टिकट देने से इनकार करने के बाद चन्नी के भाई अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चन्नी ने भाई से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा



एक परिवार, एक टिकट के नियम के अलावा, उन्हें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का भी समर्थन नहीं था, जिन्होंने डॉ मनोहर के टिकट पर दावा करने के बाद भी जीपी सिंह के समर्थन में रैली की थी। न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धू ने कहा था कि वह उन्हें शांत करने के लिए मनोहर से मिलेंगे, लेकिन मनोहर का कहना है कि सिद्धू ने उनसे कभी

मुलाकात नहीं की। इस प्रकार मनोहर की उम्मीदवारी को न केवल पार्टी और चन्नी के लिए शर्मिंदगी के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि संभवतः सिद्धू के खिलाफ चन्नी खेमे की ओर से एक बचाव के रूप में भी देखा जा रहा है। मनोहर ने कुछ पंजाबी वेब चैनलों को बताया कि चन्नी ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

मनोहर को उम्मीद, संयुक्त समाज मोर्चा करेगा उनका समर्थन लेकिन मनोहर ने कहा, मैं अपने भाई (चन्नी) से आज सुबह (रविवार) भी मिला। मैंने उनसे कहा कि मुझे जनता के साथ जाना है और वे चाहते हैं कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूं... परिवार की ओर से कोई दबाव नहीं है; मेरा निर्णय केवल जनता की इच्छा और जनता की सेवा करने की मेरी इच्छा पर आधारित है। यह गृहे जाने पर कि क्या वह किसी अन्य पार्टी का टिकट लेंगे, उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क किया गया था लेकिन जनता चाहती थी कि वह अब केवल निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ें। मुझे उम्मीद है कि संयुक्त समाज मोर्चा (किसान संघों द्वारा बनाई गई पार्टी) मेरा समर्थन करेगी जैसा कि मैंने उनके संघर्ष के दौरान किया था।

उत्तर प्रदेश / 22 जनवरी के बाद प्रचार मैदान में उतर सकते हैं अमित शाह, टिकट बंटवारे में भी निभाएंगे अहम भूमिका



नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह इस महीने की 22 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उतर सकते हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा अगले हफ्ते से ही शाह को मैदान में उतार देना चाहती है। बताया गया है कि अमित शाह अगले हफ्ते से पार्टी की चुनावी रणनीतियों तय करने के लिए कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह का यह प्रचार इसी दिन से शुरू होना है, जब चुनाव आयोग (ईसी)

गौरतलब है कि भाजपा फिलहाल पाठों राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए सही उम्मीदवारों का भी चुनाव करने में जुटी है। ऐसे में अमित शाह की यूपी में मौजूदगी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संदेश होगी। वे संपादन के नेताओं के साथ अगले प्रत्याशियों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा चुनावों में कई नेता अपने संबंधियों और रिश्तेदारों के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि, भाजपा ने फैसला किया है कि अगर पार्टी का कोई सदस्य पहले से सांसद या विधायक है, तो उसके पजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस नियम से सिर्फ उन लोगों को छूट मिलेगी, जो पहले से ही सांसद या विधायक चुने जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर चुनावी रैली पर प्रतिबंध जारी रहते हैं तो बंद जगहों पर बैठक के रास्ते अभी भी खुले हैं।

होगा, हालांकि अगर आयोग प्रचार पर लगे प्रतिबंधों को हटा लेता है, तो इससे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष को जनता के बीच जाने का मौका मिल जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा फिलहाल पांचों राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए सही उम्मीदवारों का भी चुनाव करने में जुटी है। ऐसे में अमित शाह की यूपी में मौजूदगी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संदेश होगी। वे संपादन के नेताओं के साथ अगले प्रत्याशियों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा चुनावों में कई नेता अपने संबंधियों और रिश्तेदारों के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि, भाजपा ने फैसला किया है कि अगर पार्टी का कोई सदस्य पहले से सांसद या विधायक है, तो उसके पजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस नियम से सिर्फ उन लोगों को छूट मिलेगी, जो पहले से ही सांसद या विधायक चुने जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर चुनावी रैली पर प्रतिबंध जारी रहते हैं तो बंद जगहों पर बैठक के रास्ते अभी भी खुले हैं।

गोवा चुनाव: केजरीवाल ने किया सबको रोजगार देने का वादा, कहा- जो बचेंगे उन्हें 3000 रुपये मिलेगा बेरोजगारी भत्ता



नई दिल्ली । आगामी गोवा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राज्य के दौर पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोवा के लोगों के लिए चुनाव में जीत मिलने पर ढेर सारे वादे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि गोवा में सभी को रोजगार मिलेगा, जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें तीन हजार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गोवा के लिए 13 सूत्री एजेंडे की घोषणा की है। केजरीवाल ने गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इन्हीं 13 सूत्रीय एजेंडे के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग, आजीविका, खनन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार लाएगी। दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो गोवा में हर परिवार पांच साल के भीतर सीधे 10 लाख रुपये बचाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, 1,000 रुपये प्रति

अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गोवा के लिए 13 सूत्री एजेंडे की घोषणा की है। आप ने कहा है कि सत्ता में आने पर वो इसी के तहत विकास कार्य करेगी।

माह, 40,000-50,000 रुपये से अधिक का मुफ्त स्वास्थ्य लाभ, मुफ्त शिक्षा और पानी मुहैया कराएंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के मॉडल के बारे में बात करते हुए, आप नेता ने कहा- दिल्ली की तरह, गोवा के हर गांव और जिले में बेहतर और

मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लिए मोहल्ल क्लिनिक और नर्स्याल खोले जाएंगे। आगे केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने आप को आजादी के बाद से 'भारत की सबसे ईमानदार पार्टी' का सर्टिफिकेट

विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ समस्त देश व प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि

‘सबका साथ-सबका विकास’ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व व कर्तव्यनिष्ठ से आज भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस मह्वाभियान की

वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। इस टीकाकरण में भारत अब



विश्वभर में पहले स्थान पर है। अभी तक देश में 156.59 करोड़ कुल टीकाकरण हुआ है। इसके साथ-साथ भारत में टीकाकरण अभियान विश्व के दूसरे देशों की तुलना में तीव्र गति से भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टीकाकरण

अभियान में कई रिकॉर्ड भी बने हैं। टीकाकरण के पहले दिन विश्व स्तर पर टीका पाने वाले नागरिकों की संख्या भारत में सर्वाधिक थी। इसके अलावा 17 सितंबर 2021 को एक ही दिन में 2.5 करोड़ डोज के साथ सर्वाधिक

टीकाकरण हुआ। सबसे तेज टीकाकरण अभियान के तहत एक साल में वैक्सीन के 156 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। इन सबके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ायी सोच का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश

में भी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा जा रहा है। अब तक 2 करोड़ 12 लाख 3 हजार 919 लोगों को पहली डोज व 1 करोड़ 58 लाख 33 हजार 825 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2.34 लाख करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली । सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह 2,34,161.58 करोड़ रुपये का जोरदार उछाल आया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सबसे अधिक लाभ में रहें। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 1,478.38 अंक या 2.47 प्रतिशत चढ़ा। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान रिलायंस

इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 69,503.71 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 17,17,265.94 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इन्फोसिस के बाजार मूल्यंकन में 48,385.63 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 8,10,927.25 करोड़ रुपये रहा। इसी तरह टीसीएस की बाजार हैसियत 42,317.15 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 14,68,245.97 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। एचडीएफसी का



मूल्यंकन 21,125.41 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 4,91,426.13 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का 18,650.77 करोड़ रुपये

के लाभ से 5,69,511.37 करोड़ रुपये रहा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का बाजार पूंजीकरण 15,127.22 करोड़ रुपये के उछाल

से 4,53,593.38 करोड़ रुपये पर और बजाज फाइनेंस का 10,291.28 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 4,72,686.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। समीक्षाधीन सप्ताह में भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 8,760.41 करोड़ रुपये बढ़कर 3,95,810.41 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इस रुख के उलट हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 12,217.88 करोड़ रुपये के नुकसान से 5,55,560.85

करोड़ रुपये रह गया। एचडीएफसी बैंक का मूल्यंकन 2,854.33 करोड़ रुपये घटकर 8,56,439.28 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक और भारती एयरटेल का स्थान रहा।

बजट के इंतजार और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के बीच कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? जानें एक्सपर्ट राय



नई दिल्ली । देश में ओमीक्रॉन संक्रमण की अपेक्षाकृत कम भयावह स्थिति, तेज टीकाकरण और मजबूत आर्थिक संकेत की बदौलत बीते सप्ताह ढाई प्रतिशत की छलांग लगा चुके शेयर बाजार पर अगले सप्ताह वैश्विक संकेत, कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के परिणाम और बजट पूर्व उम्मीदों का असर रहेगा। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयर्स वाला सवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1478.38 अंक यानी 2.47 प्रतिशत की उछाल लेकर ढाई महीने बाद 61 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार

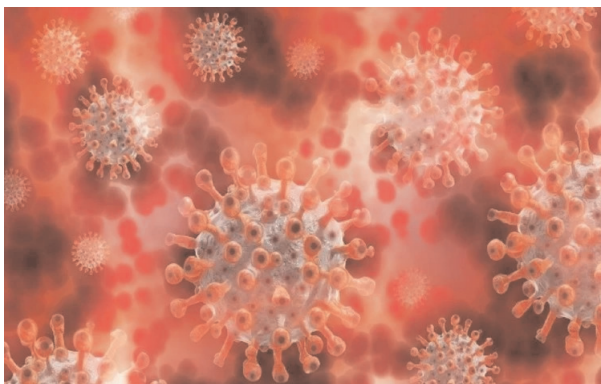
61223.03 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का नफ्टी 443.05 अंक अर्थात 2.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 18 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर 18255.75 अंक पर रहा। इसी तरह दमिज कंपनियों की तरह छोटी और मझौली कंपनियों में जमकर लिवाली हुई।

बीएसई का मिडकैप 2.4 प्रतिशत मजबूत होकर 26085.24 अंक और स्मॉलकैप 3.06 प्रतिशत की छलांग लगाकर 30951.28 अंक पर रहा। आलोच्य सप्ताह शेयर बाजार में लगातार चार दिन तेजी रही

जबकि अंतिम कारोबारी दिवस इसकी बढ़त पर ब्रेक लग गया। विश्लेषकों का कहना है कि बीता सप्ताह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के तिमाही परिणाम हो लेकर सकारात्मक रहा और अगला सप्ताह भी मजबूत आय के मामले में एक महत्वपूर्ण सप्ताह होने जा रहा है। सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शनिवार को जारी हो चुके परिणाम का बाजार पर असर दिखेगा वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और हिंदुस्तान यूनिलीवर के परिणाम अगले सप्ताह जारी होंगे, जिसका असर बाजार पर अवश्य रहेगा।

उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में बजट से पहले की पहल शुरू हो गई है और इसके अगले सप्ताह भी जारी रहने से संभावना है। वैश्विक बाजार में कुछ अस्थिरता दिख रही है, जिसका फेरलू बाजार पर भी कुछ प्रभाव दिख सकता है। हालांकि कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं है क्योंकि संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर बहुत कम है।

संक्रमण बढ़ने से बाधित हो सकती है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ईईपीसी इंडिया ने जाहिर की ये बड़ी चिंता



नई दिल्ली । कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई राज्यों में इसके चलते प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है, वहीं अब भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी इंडिया) ने भी ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की चिंता जाहिर की है। ईईपीसी इंडिया ने का कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का प्रकोप बढ़ने से एक बार फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिसका असर व्यापारिक गतिविधियों

में मंदी के रूप में सामने आ सकता है। इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में दिसंबर, 2021 के दौरान सालाना आधार पर 38 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 38.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष महेश देसाई ने शुक्रवार को कहा कि लगातार वृद्धि से पता चलता है कि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की राह पर है। देसाई ने कहा कि आने वाले वक्त के लिए ऑर्डर अच्छे हैं, लेकिन यदि ओमीक्रोन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती है, तो हम कुछ वक्त के लिए मंदी का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दुनियाभर में महामारी के प्रकोप के चलते हाल के हफ्तों में अस्थिरता और अनिश्चितता के कुछ संकेत देखे हैं, लेकिन सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिये व्यापार को गति दे सकती है। उन्होंने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की सरकार से अपील भी की है।

ऑयल इंडिया इस अमेरिकी कंपनी से बाहर निकली, इतने में हुई डील

(वेब वार्ता)

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) अमेरिका के शेल तेल उद्यम से बाहर निकल गई है। कंपनी ने इस उपक्रम में अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी 2.5 करोड़ डॉलर में उद्यम भागीदार को बेच दी है। इस तरह दो महीने में अमेरिकी शेल कारोबार से बाहर निकलने वाली यह दूसरी भारतीय कंपनी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक (ओआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) ने नियोजनार शेल संपत्तियों में अपनी समूची हिस्सेदारी बेच दी है। ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (ओआईसी) ने संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2012 में कोलोराडो में ब्लूस्टन स्थित कैरिजो ऑयल एंड गैस की नियोजनार शेल संपत्ति में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी 8.25 करोड़ डॉलर में खरीदी थी। ओआईएल की अनुषंगी ने जहां 20

प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, वहीं आईओसी ने अपनी संबंधित अनुषंगी कंपनी के माध्यम से कैरिजो के नियोजनार बेसिन की संपत्ति में 10 प्रतिशत हस्सिल की थी। कुल 8.25 करोड़ डॉलर के निवेश में 4.12 करोड़ डॉलर का अग्रिम भुगतान शामिल था। इसके अलावा शेष 4.12 करोड़ डॉलर का भुगतान कैरिजो की भविष्य की ड्रिलिंग और विकास की लागत से जुड़ा था। ऑयल इंडिया ने यह यह हिस्सेदारी वेस्टाद रिसेसर्सेज एलएलसी को बेची गई है जो इस संपत्ति की परिचालक है। कैरिजो ने जनवरी, 2018 में नियोजनार संपत्ति की बिस्की वेस्टाद रिसेसर्सेज को की थी। उसके बाद वह इस संपत्ति की नई परिचालक बन गई थी। ओआईएल से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में शेल संपत्तियों से बाहर निकलने की घोषणा की थी। अमेरिकी शेल संपत्तियों में रिटर्न आकर्षक नहीं रहने की वजह से रिलायंस ने यह कदम उठाया था।

आज देश का पहला स्टार्टअप डे: देश में 60 हजार से ज्यादा स्टार्टअप, इनमें से 44 यूनिकॉर्न; इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत ऊपर आ रहा

नई दिल्ली । आज से हर साल 16 जनवरी को देश में स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इसका एलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि स्टार्टअप की यह संस्कृति देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने देश की स्टार्टअप यूनित्स को नए भारत का आधार-स्तंभ बताया है। पीएम मोदी ने आंत्रप्रेन्योरशिप, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से मुक्त कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इनोवेश को प्रमोट करने के लिए इस्टीमेट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना बेहद जरूरी है। स्टार्टअप भारत के बैकबोन बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013-14 में



जहां चार हजार पेटेंट को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले साल इनकी संख्या 28 हजार से ज्यादा हो गई। देश में अब 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप यूनित्स हैं। इनमें से 44 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न का मतलब ये

होता है कि उस स्टार्टअप का वैल्यूएशन 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश सरकार की प्राथमिकता है। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है

जिसने अभी कामकाज शुरू किया है। आप अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं, जिसे इनक्यूबेशन कहते हैं। यहां पर लोग अपनी-अपनी कुशलता और विशेषज्ञता लेकर आते हैं। नए कारोबारी आईडिया पर मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनी के जरिए ग्राहकों को एक यूनिट प्रोडक्ट या सर्विस दी की जाती है। स्टार्टअप सफल होने के बाद एक बड़ी कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना लेते हैं। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसका प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। 2015 में इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 81 थी। अब उसकी रैंकिंग 46 है। यानी भारत की रैंकिंग में 35 पायदान का सुधार हुआ है।

एटीएफ के दाम 4.2 प्रतिशत बढ़े, लगातार 72वें दिन फ्यूल की कीमतों में बदलाव नहीं

नई दिल्ली । वाहन ईंधन 4.2 प्रतिशत महंगा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच इस महीने में दूसरी बार एटीएफ के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं वाहन ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 72वें दिन बदलाव नहीं हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अभिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतें 3,232.87 रुपये प्रति किलोलिटर या 4.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 79,294.91 रुपये प्रति किलोलिटर पर पहुंच गई हैं। नए साल यानी जनवरी में यह एटीएफ कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले एक जनवरी को विमान ईंधन के दाम 2,039.63 रुपये प्रति किलोलिटर या 2.75 प्रतिशत बढ़ाए



गए थे और यह 76,062.04 रुपये

प्रति किलोलिटर पर पहुंच गया था।

वहीं दिसंबर में एटीएफ कीमतों में

दो बार कटौती की गई थी। उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम नीचे आए थे। उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। नवंबर के मध्य में जेट ईंधन 80,835.04 रुपये प्रति किलोलिटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था। एक और 15 दिसंबर को एटीएफ कीमतों में कुल मिलाकर 6,812.25 रुपये प्रति किलोलिटर या 8.4 प्रतिशत की कटौती की गई थी। जेट ईंधन की कीमतों में हर महीने की एक और 16 तरीख को संशोधन किया जाता है। वहीं पेट्रोल और डीजल कीमतों में प्रतिदिन संशोधन होता है।लेकिन वाहन ईंधन कीमतों में चार नवंबर, 2021 से बदलाव नहीं हुआ है। उस समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पांच रुपये और डीजल पर

10 रुपये प्रति लीटर घटाया था। हालांकि, इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट कच्चे तेल के दाम में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। ब्रेंट कच्चा तेल पांच नवंबर, 2021 को 82.74 डॉलर प्रति बैरल पर था। एक दिसंबर को यह घटकर 68.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। उसके बाद से इसके दाम बढ़ रहे हैं और यह 85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उत्पाद शुल्क कटौती से पहले देशभर में वाहन ईंधन के दाम सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गए थे। ज्यादातर शहरों में पेट्रोल ने 'शतक' लगा दिया था। वहीं डीजल भी कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया था।

एक नजर

भारत से मदद मिलने के बाद क्या दूर हो जाएंगी श्रीलंका की समस्याएं? एक्सपर्ट की है ये राय

नई दिल्ली । भारत के वित्तीय पैकेज ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया है। श्रीलंका के शीर्ष अर्थशास्त्री डब्ल्यू विजयवर्द्धने ने शनिवार को यह बात कही। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि देश में विदेशी मुद्रा संकट के मद्देनजर गोटबाया राजपक्षे सरकार को तत्काल अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से मदद लेने की जरूरत होगी। इस द्वीपीय देश में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी के बीच भारत ने बृहस्पतिवार को श्रीलंका को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्य आयात के लिए 90 करोड़ डॉलर के ऋण की घोषणा की है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजीत निवाई केब्राल से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर के साथ मुलाकात में पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक द्वारा दी गई 90 करोड़ डॉलर से अधिक की ऋण सुविधा के बीच भारत की ओर से श्रीलंका को समर्थन का भरोसा दिलाया। विजयवर्द्धने ने कहा कि भारत की समय पर सहायता ने श्रीलंकाई सरकार को दो महीने की राहत दी है। इस दौरान कठिन आर्थिक सुधारों को लागू करने और स्थानीय समाधान के लिए आईएमएफ से एक बेलआउट की आवश्यकता है।उन्होंने कहा, भारत के हस्तक्षेप से श्रीलंका को मदद मिली है, लेकिन वे हमें संकट से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें भारत से मिली मदद का सम्मान करते हुए आईएमएफ से मदद लेने की जरूरत है। विजयवर्द्धन की टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे द्वारा शनिवार को श्रीलंका को भारतीय आर्थिक सहायता पर एक व्यापक वर्चुअल बैठक के बाद आई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान जयशंकर ने बताया कि भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है, और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक और अन्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए वह उसका हस्तक्षेप तरीके से समर्थन जारी रखेगा। आईएमएफ से राहत प्राप्त करने का मुद्दा विवादास्पद रहा है, जिसको लेकर श्रीलंकाई मजिस्ट्रेट ने काफी मतभेद है।

इलेक्ट्रिक वाहन वार्जिंग को लेकर सरकार ने बदले नियम, ये है पूरा प्लान

नई दिल्ली । बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के तेजी से प्रसार में मदद मिलेगी। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत ईवी मालिक अपने निवास या कार्यालय के मौजूद बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल कर इन वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इसके अलावा ईवी चार्जिंग अवसरचना की स्थापना को लाइसेंस मुक्त भी कर दिया गया है। बिजली मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, “केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसरचना के संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं।” बयान में कहा गया कि इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सुरक्षित, भरोसेमंद, सुलभ और किफायती चार्जिंग ढांचे को बढ़ावा देना है, ताकि देश तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सके। बयान के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी लाइसेंस अनिवार्यता के बिना ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे स्टेशन तकनीकी के साथ सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा करते हों। इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि की अवधि में चार्जिंग स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमतों को राजस्व भागीदारी मॉडल बनाया गया है। सरकारी/सार्वजनिक इकाइयों के पास मौजूद जमीन को सार्वजनिक/सरकारी इकाइयों को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) लगाने के लिए राजस्व भागीदारी मॉडल के आधार पर दिया जाएगा। इसके तहत भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसी को एक रुपये/केडब्ल्यूएच की निश्चित दर पर भुगतान किया जाएगा। पीसीएस यह भुगतान तिमाही आधार पर करेंगे। दिशानिर्देशों में आदर्श राजस्व भागीदारी करार को शामिल किया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए अलर्ट, 1 फरवरी से लागू हो रहा ये नियम

नई दिल्ली । अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, आगामी 1 फरवरी से बैंक के चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियम में बदलाव होने वाला है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अनिवार्य होगा, वनां पंरशानी हो सकती है। अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक को वापस भी किया जा सकता है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है-हमारा सुझाव है कि आप सीटीएस क्लीयरिंग के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा का लाभ लें। विभिन्न माध्यमों से विवरणों की पुनः पुष्टि कर स्वयं को धोखाधड़ी से बचाएं। पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्चुअल मोबाइल नंबर 8422009988 की सुविधा दी है। सीपीपीएस लिखने के बाद अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक डेट, चेक अकाउंट, ट्रान्जेक्शन कोड, पेयी के नाम के साथ 8422009988 पर भेजने पर कंफर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800 258 4455 और 1800 102 4455 पर फोन किया जा सकता है। आपको बता दें कि चेक का कंफर्मेशन किसी एक ही मोड से देना है। वहीं, कंफर्मेशन की तारीख से 3 महीने पुराने चेक को नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य के किसी तारीख के चेक को स्वीकार किया जाएगा।

इस तारीख को पेश होगा बजट 2022, ये रही दिन और समय सहित जरूरी जानकारी

नई दिल्ली । अगर आप आम बजट 2022 के पेश किए जाने की तारीख और समय को लेकर कम्प्यूज हैं कि कहीं कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और संसद के सैकड़ों कर्मचारियों के पॉजिटिव होने के कारण बजट को फिलहाल के लिए टाल तो नहीं दिया जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत सरकार द्वारा हर बार की तरह ही इस बार भी एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आम तौर पर हर साल एक फरवरी को ही वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। इस साल भी ऐसा ही होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट की घोषणा करेंगी। बजट पेश करने को लेकर सुबह से ही दिल्ली में हलचल रहेगी लेकिन आम तौर पर संसद में बजट पेश होते-होते दोपहर हो जाती है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि, बीच में एक महीने का अवकाश होगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू होकर 11 फरवरी को समाप्त होगा। इसी दौरान बजट भी पेश होगा। फिर एक महीने के अवकाश के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल को समाप्त होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण संसद के कर्मचारियों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। बीते 9 से 12 जनवरी के बीच संसद के 300 से अधिक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 400 से अधिक कर्मचारी औचक परीक्षणों के दौरान संक्रमित पाए गए थे। सूत्रों ने बताया कि अब तक लगभग 718 संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि, लोकसभा सचिवालय के मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर का निरीक्षण करने के बाद कहा था कि स्थिति नियंत्रण में है और महामारी से मुकाबला करने के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं। बिरला ने कहा था, “संसद के 2022 के बजट सत्र के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि संसद अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वह कर सकें।”

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए कितनी रहीं आज की कीमतें

नई दिल्ली । सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज 47 दिन के बाद भी दाम स्थिर हैं। पिछले कई महीनों से देश कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। देश में तेल के दाम अभी आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये व डीजल की कीमत 94.14 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 रुपये जबकि डीजल का दाम 89.79 रुपये लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.40 रुपये लीटर है तो डीजल 91.43 रुपये लीटर है। बता दें कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है।

एक नजर

देशत्यापी टीकाकरण को एक साल पूरे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से जानिए कैसे सफल बना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान

नई दिल्ली । कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान ने रविवार यानी 16 जनवरी को एक साल पूरा कर लिया है। इस पूरे एक साल के दौरान टीके की करीब 156.76 करोड़ खुराकें दी गईं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे सफल अभियान बताते हुए पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान सबसे प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। इसके साथ ही मंडाविया ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक करीब 92 प्रतिशत वयस्क आबादी को कम से कम एक खुराक मिल गई है जबकि करीब 68 प्रतिशत का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। केंद्र टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रविवार दोपहर का एक डक टिकट जारी करेगा। अभियान पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था, जब पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराकें दी गई थीं। इसके बाद अग्रिम मोर्चा के कर्मियों के लिए टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था। कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से शुरू हुआ जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों को टीका लगाया गया जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां थीं। अभियान के अगले चरण में 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण एक अप्रैल से शुरू हुआ था। सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण की अनुमति देकर अभियान का दायरा एक मई 2021 से और बढ़ा दिया था। इसके बाद 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का अगला चरण इस साल तीन जनवरी से शुरू हुआ। भारत ने स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पॉिक के कार्यकर्ताओं को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देना 10 जनवरी से शुरू कर दिया, जिसमें मतदान वाले पांच राज्यों में तैनात मतदान कर्मी और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के प्रसार को रोकने की कवायद के तहत एहतियाती खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि टीकाकरण के लिए काफी कम जनसंख्या वाले कई विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में भारत का टीकाकरण कार्यक्रम सबसे सफल और सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक रहा है। रविवार सुबह सात बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोविड-19 टीकाकरण के तहत 156.76 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। 43.19 लाख एहतियाती खुराकें देने के साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग के 3,38,50,912 लाभार्थियों को पहली खुराक दी जा चुकी है।

पीएम मोदी ने आप को दिया ईमानदारी का प्रमाण पत्र, केजरीवाल का केंद्र पर तंज

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) 1947 के बाद से देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, यह दावा करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है। केजरीवाल इन दिनों गोवा में पार्टी के लिए जोर-शोर पर प्रचार में व्यस्त हैं। आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में प्रवास पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीएम मोदी ने आप को आजादी के बाद से भारत की सबसे ईमानदार पार्टी का प्रमाण पत्र दिया है। मोदी जी ने सीबीआई, पुलिस से मुझ पर और मनीष सिंसोदिया पर छापा मारा। 21 पार्टी विधायकों को गिरफ्तार किया गया, 400 फाइलों की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। फिर भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमारे डीएनए में है। इसके अलावा 14 फरवरी को होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की जनता के समक्ष 13 सूत्री एजेंडा भी रखा। केजरीवाल ने कहा, -गोवा की जनता 14 फरवरी को होने वाले चुनावों का इंतजार कर रही है। लोगों के लिए आम आदमी पार्टी नई उम्मीद है। उनके पास पहले भाजपा/कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वे बदलाव चाहते हैं और निराश हैं। आप के 13 सूत्री एजेंडे के तहत केजरीवाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जिन्हें नहीं मिलेगा उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि बेहतर और मुक्त स्वास्थ्य सेवा के लिए गोवा के हर गांव और जिले में मोहल्ल क्लीनिक और अस्पताल खोले जाएंगे। किसान समुदाय के साथ चर्चा के बाद खेती के मुद्दों को हल किया जाएगा। व्यापार प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रदान करेंगे। पर्यटन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। गोवा में 24म7 मुफ्त बिजली और पानी होगा। सड़कों में सुधार किया जाएगा और सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि राज्य में खनन का बहुत बड़ा निहित स्वार्थ है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सत्ता में आती है तो वह छह महीने में लोगों को जमीन का अधिकार देा।

क्या दिल्ली में कोरोना का पीक खत्म हो गया? एक्सपर्ट्स बोले- यह हॉस्पिटलाइजेशन से तय नहीं होगा

नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना केस और पाॉजिटिविटी रेट में बीते कई दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन अपेक्षाकृत कम है। विशेेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में कोरोना की यह लहर खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि हॉस्पिटलाइजेश से पता चलता है कि मौजूदा लहर चरम पर है और मामले जल्द ही कम हो सकते हैं। हालांकि, जाने-माने महामारी विज्ञानी डॉ चंद्रकांत लहरिया के अनुसार अस्पताल में दाखिल के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पीक खत्म हो गई है। इसका कारण यह है कि लोग बीमारी के विकसित होने के कुछ दिनों बाद ही अस्पताल में भर्ती होते हैं। इसमें 6-7 दिनों का अंतराल है। उन्होंने कहा, दैनिक मामलों की संख्या और सकारात्मकता दर का इस्तेमाल पीक तय करने के लिए किया जाना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन एंट्री के लिए बनाए गए मानदंडों पर निर्भर करता है। बेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए हॉस्पिटलाइजेशन अहम पैरामीटर है, लेकिन यह महामारी के पीक को तय नहीं कर सकता है। जोधपुर स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंप्लिमेंटेशन रिसर्च के डायरेक्टर डॉ अरुण शर्मा ने कहा, महामारी विज्ञान में एक लहर की पीक संचरण की दर, संक्रमित लोगों की संख्या और असंक्रमित अतिवसंदेनशील आबादी के आधार पर तय होती है। इसे एक ग्राफ पर प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा महामारी विज्ञान मॉडलिंग से अलग होती है। डॉ. शर्मा ने कहा कि पाॉजिटिविटी रेट सबसे अहम फैक्टर है, क्योंकि किए गए टेस्ट्स की संख्या के आधार पर मामलों की संख्या बढ़ या घट सकती है। जब सकारात्मकता दर घटने लगेगी, तो हमें पता चलेगा कि हमने पीक को पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऑमिक्रॉन में ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में लहर चरम पर है या नहीं, यह हॉस्पिटलाइजेशन को देखकर नहीं तय हो सकता है।

केब सर्विस और डिलीवरी सेवाओं वाली कर्पनियों को अपनाने होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, दिल्ली सरकार की झूफ्ट पॉलिसी अधिसूचित

नई दिल्ली। दिल्ली में ई-कॉमर्स सेवा, खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाली और केब सुविधा देने वाली सभी कर्पनियों को नए वाहन खरीदते समय अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने होंगे। दिल्ली सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक एग्रीगेटेड पॉलिसी को झूफ्ट को अधिसूचित किया, जिसके तहत यहड एग्रीगेटेड और डिलीवरी सेवाओं को नए बड़े की खरीद के दौरान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार भारत में ईवी बड़े को अनिवार्य करने के लिए एग्रीगेटर नीति मसौदा तैयार करने वाली

पहली सरकार बन गई है। मसौदा नीति को 60 दिनों के लिए जनता की राय के लिए रखा गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नीति एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से पांच प्रतिशत अगले तीन महीनों में विद्युत चालित वाहन हों, जबकि मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25

प्रतिशत वाहन विद्युत चालित हों। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश और मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों के लिए बिजली की आपूर्ति मार्च 2025 तक औसत लागत की दर पर दी जाएगी और शुल्क का निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी। शुक्रवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तिगत अपने घर या कार्यालय में अपने बिजली कनेक्शन से चार्जिंग कर सकेंगे। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे सुरक्षा और सुविधा संबंधी नियमों के

अनुसार चलना होगा और बिजली मंत्रालय, ऊर्जा दक्षत ब्यूरो और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानकों के अनुसार सामान लगाने होंगे। इन दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में किसी भी देशी-विदेशी या नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पर लम्बी दूरी के वाहनों की चार्जिंग की भी सुविधा होगी। सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों को वित्तीय दृष्टि से घर या कार्यालय में अपने बिजली कनेक्शन से चार्जिंग कर सकेंगे। यही शुल्क बैटरी चार्जिंग स्टेशन के लिए भी लागू होगा। इन केंद्रों पर चार्जिंग शुल्क की अधिकतम दर राज्य सरकारें तय करेंगी क्योंकि वे इनके लिए

एक रुपये की स्थिर दर से हिस्सा दिया जा सकता है। जमीन का पहला समझौता दस साल के लिए चाहना चाहिए। महानगरों में ऐसे सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों के लिए स्टेशन बिजली का कनेक्शन नियमों के अनुसार सात दिन में और अन्य शहरों में 15 दिन के अंदर देना होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चार्जिंग केंद्रों के लिए 31 मार्च 2025 तक बिजली आपूर्ति की दर व्यावहारिक बनाने के लिए जमीन को राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था के तहत प्रयोग की छूट दी गई है। सरकारी एजेंसियों इसके लिए अपने पास उपलब्ध जमीन दे सकती है और उ्हें प्रति यूनिट चार्ज के लिए

रियायती दर पर बिजली दे रही होंगी और इन केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य तथा केंद्र से सब्सिडी भी मिल रही होगी। कोई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, चैन चार्जिंग स्टेशन विद्युत उत्पादन कंपनी से बिजली की खरीद सकेगा। इसके लिए आवेदन अंदर देना होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चार्जिंग केंद्रों के लिए 31 मार्च 2025 तक बिजली आपूर्त की दर व्यावहारिक बनाने के लिए जमीन को राजस्व स्तरीय नोडल एजेंसियों से परामर्श स्टेशन के लिए भी लागू होगा। इन केंद्रों पर चार्जिंग शुल्क की अधिकतम दर राज्य सरकारें तय करेंगी क्योंकि वे इनके लिए

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों को चार्जिंग का समय दूरसंचार सुविधाओं के माध्यम से अग्रिम बुक करने की सुविधा देनी होगी और इसके लिए उन्हें कम से कम एक ऑनलाइन नेटवर्क सर्विस कंपनी के साथ समझौता करना होगा। शहरों में तीन किलोमीटर के दायरे में ऐसा कम से कम एक केंद्र जरूर रहेगा। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ स्टेशन स्थापित होंगे। नए दिशानिर्देश अक्टूबर 2019 में जारी दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित कर देंगे।



परेशानियों से जूझ रहे कोरोना योद्धा के परिजन, इयूटी के दौरान संक्रमित होने से गई थी जान; कई परिवारों पर हो गया है लाखों का कर्ज

नई दिल्ली। महामारी की तीसरी लहर की गिरफ्त में आ चुकी राज्य सरकार दूसरी लहर में शहीद हुए कोरोना योद्धाओं के परिजनों को भूल गई है। वे आज भी भटक रहे हैं। परिवारों का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनको पछने वाला कोई नहीं है। जहां डाक्टरों को कोरोना इयूटी के दौरान संक्रमण होने पर इलाज का खर्च नहीं दिया गया वहीं उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार या बुजुर्ग मां-बाप को आर्थिक सहायता तक नहीं मिली। वे इसके लिए भटक रहे हैं। इन भटकने वालों में नर्सों के अलावा अन्य कर्मचारियों के परिजन भी हैं। दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में काम कर चुके भूतपूर्व नर्सिंग अधिकारी राजकुमार भगपाल



कि उनको भी सरकार की तरफ से पूरी मदद नहीं मिल पाई। डॉ. अमित गुप्ता कोरोना वार्ड में इयूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद कई महीने

इलाज के लिए भटकने के बाद दम तोड़ दिए थे। इलाज का संघर्ष करते हुए पिता पर लाख करोड़ रुपए का कर्ज आ गया। एक ईसीजी चलाने

दिल्ली में आ सकते हैं 17,000 मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब मिलेगी कोरोना प्रतिबंधों में ढील



नई दिल्ली । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) के लगभग 17,000 मामले आ सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों के लिए एक और राहत भरी खबर बताते हुए, जैन ने कहा कि मामले की संक्रमण दर में भी गिरावट देखने की संभावना है। पिछले दो दिनों से, दिल्ली में दैनिक मामले 28,000 से नीचे बने हुए हैं। गुरुवार को, कोविड-19 के 28,867 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक एक दिवसीय बढ़ोतरी थी।

जैन ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंच चुका है और सरकार एक बार दैनिक मामलों में गिरावट 15,000 तक पहुंच जाए तो प्रतिबंधों को वापस ले लेगी। उन्होंने कहा, हम कह सकते हैं कि कोरोना मामले दिल्ली में पीक पर पहुंच गए हैं। मामले कम होने लगे हैं। देखते हैं कब गिरावट आती है। दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। सप्ताह के दिनों में रेस्तरां और बार में डाइन-इन सेवाओं को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर सीमा लगाया है, जबकि सप्ताहांत के दौरान केवल टेकअवे की अनुमति है। दुकानें ऑड-इन के आधार पर खुल रही हैं और केवल 20 लोगों को शांदि्यों और अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति है। आवश्यक और छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, लगभग 1,58,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, 25,335 लोगों की मौत हो चुकी है और सक्रिय मामले 93,407 हैं।

प्रधानमंत्री के “शानदार नेतृत्व” ने 92 प्रतिशत आबादी को कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है



नई दिल्ली । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश की विशाल आबादी का टीकाकरण असंभव लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के “शानदार नेतृत्व” ने इसे संभव बनाया और देश की सबसे अधिक उम्र के लोगों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों को टीका लगाया गया जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां थीं। अभियान के अगले चरण में 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण एक अप्रैल से शुरू हुआ था। सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण की अनुमति देकर अभियान का दायरा एक मई 2021 से और बढ़ा दिया था। इसके बाद 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों के लिए

कोविड-19 टीकाकरण अभियान का अगला चरण इस साल तीन जनवरी से शुरू हुआ। भारत ने स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पॉिक के कार्यकर्ताओं को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देना 10 जनवरी से शुरू कर दिया, जिसमें मतदान वाले पांच राज्यों में तैनात मतदान कर्मी और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के प्रसार को रोकने की कवायद के तहत एहतियाती खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि टीकाकरण के लिए काफी कम जनसंख्या वाले कई विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में भारत का टीकाकरण कार्यक्रम सबसे सफल और सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक रहा है। रविवार सुबह सात बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोविड-19 टीकाकरण के तहत 156.76 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। 43.19 लाख एहतियाती खुराकें देने के साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग के 3,38,50,912 लाभार्थियों को पहली खुराक दी जा चुकी है।

आपसी समझौते से पिता-पुत्र ने खत्म की रार, दिल्ली हाईकोर्ट भी एफआईआर रद्द करने को तैयार



नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता-पुत्र द्वारा अपने आपसी मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से दूर करने के बाद बेटे की शिकायत पर पिता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया है। एफआईआर में बेटे ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने उसे तब मारा जब उसने घर के मेन गेट के सामने अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेलने पर आपत्ति जताई, जहां से घर की महिलाएं भी गुजरती हैं। जस्टिस मुका गुप्ता ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाले व्यक्ति को स्वीकार करके हुए कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों ने बिना किसी जोर जबर्दस्ती और दबाव के अपनी इच्छा से मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और आगे कार्यवाही जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह उनके बीच और कटुता पैदा करेगा, उपरोक्त



एफआईआर और उसके अनुसार कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में होगा। अदालत कहा कि इस प्रश्न में एफआईआर को रद्द करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अदालत ने कहा कि परिणामस्वरूप, थाना- न्यू उसमानपुर में दर्ज आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत एफआईआर संख्या 707/2018 और उसके अनुसार कार्यवाही रद्द की जाती है। अदालत

साथ शतरंज खेल रहे थे। उसने अपने पिता से कहा कि घर में बहू-बेटियों और बच्चों सहित परिवार के अन्य सदस्य भी हैं और उन्हें दरवाजे के ठीक सामने नहीं बैठना चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्य उसी दरवाजे से आ सकें और जा सकें। एफआईआर में कहा गया कि यह सुनकर उसके पिता भड़क गए और शिकायतकर्ता को मारा जिससे वह घायल हो गया। शिकायतकर्ता की पत्नी उसे अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज किया गया। पिता और पुत्र एक ही घर में और अलग-अलग मर्जिलों पर रह रहे हैं और 13 दिसंबर, 2021 को आपसी समझौते के जरिए मामले को सुलझा लिया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि वह अपने पिता यानी याचिकाकर्ता के हर कृत्य पर आपत्ति न करके भविष्य में भी सावधान रहेगा और शांति और सद्भाव से साथ रहेगा। शिकायतकर्ता ने पक्षों के बीच हुए समझौते की शर्तों का पालन करने का वचन दिया था।

दिल्ली में साजिश : गाजीपुर आए सँदिग्ध लड़कों की तलाश जारी, आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का भी लगा रहे पता

नई दिल्ली । गणतंत्र दिवस से पूर्व देश के तीन राज्यों दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में मिले विस्फोटक को आतंकियों की कतारुत माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीमापार बैठे आतंकी संगठन देश में गड़बड़ी पैदा करने की नयित से बड़े हमले की फिन्क में है। शुक्रवार को गाजीपुर मंडी से मिले आईईडी में आरडीएक्स होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको जांच के लिए सीएफएसएल भेजा गया है। उसके बाद ही साफ हो



लड़कों के दो समूह मंडी में सँदिग्ध हालात में दिखाई दिए। इनकी पहचान सीसीटीवी कैमरों से की गई। इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया जा रहा है कि लड़कों के यह समूह रेजना अपने काम से तो मंडी नहीं आते। इसकी पुष्टि करने के लिए मंडी के कर्मचारियों व आदृतियों से भी मदद ली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन लोगों को इस घटना में हाथ हो सकता है। इसलिए उनकी तलाश की

जा रही है। दूसरी ओर चौकी गाजीपुर मंडी का एरिया बिस्कूल दिल्ली-यूपी की सीमा से सटा हुआ है। इसलिए यूपी और दिल्ली पुलिस दोनों से मामले की जांच के लिए मदद ली जा रही है। यूपी व दिल्ली के लोकल थाना पुलिस से उनके इलाके के लोकल बदमाशों की सूची भी तैयार कर मांगी गई है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आईईडी रखने के लिए किसी लोकल बदमाश का सहयोग लिया गया हो।

सम्पादकीय

दक्षिण अफ्रीका : डेसमंड टूटू की विरासत

पिछले कुछ हफ्तों से मैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में विचार कर रहा था, क्योंकि वहां टेस्ट थ्रूखला खेली जा रही थी, लेकिन इसकी बड़ी वजह थे आर्कबिशप डेसमंड टूटू. पिछले हफ्ते जिनका निधन हो गया और उनके साथ ही रंगभेद विरोधी संघर्ष के अंतिम महान योद्धा की विदाई हो गई। संभवतः वह अपने किसी भी समकालीन की तुलना में विश्व की अंतरात्मा के अधिक करीब थे। मैंने डेसमंड टूटू को पहली बार जनवरी, 1986 में टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा था। तब मैं अमेरिका में अध्यापन करता था और वह पादरी उस देश के प्रवास पर थे, ताकि वह अमेरिका और अमेरिकियों को झकझोर सकें, जो कि मौन और कई बार मुखर होकर नस्लवादी सत्ता का समर्थन कर रहे थे। टूटू मानते थे कि पश्चिम का आर्थिक दबाव सत्तारूढ़ व्यवस्था को नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए कदम उठाने को मजबूर कर देगा। वहां वह कॉरपोरेट प्रमुखों से मिले, जिनमें जनरल मोटर्स के प्रमुख भी शामिल थे, उनके अलावा उन्होंने अमेरिका के सबसे महान और सबसे समृद्ध विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से भी मुलाकात की और उनसे दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर किए गए लाभप्रयक निवेश को वापस लेने का आग्रह किया। वहां उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से भी की जा रही थी, जिसे इस दक्षिण अफ्रीकी ने खारिज कर दिया और पत्रकारों से कहा कि अन्य चीजों के अलावा एमएलके (मार्टिन लूथर किंग) उनकी तुलना में खूबसूरत थे। यह कहते हुए उन्होंने अपने नाटं कद और गोलमटोल शरीर और बिखरे बालों का हवाला दिया। दक्षिण अफ्रीका में निवेश करने वाले अमेरिकी विश्वविद्यालयों में येल भी था, जहां मैं काम कर रहा था। टूटू के प्रवास ने छात्रों के साथ ही शिक्षकों के एक वर्ग को भी प्रभावित किया, जिन्होंने येल कॉरपोरेशन से संपर्क कर उनसे दक्षिण अफ्रीका कर्पनियों से निवेश खींचने का आग्रह किया। कॉरपोरेटर्स ने दम्भपूर्ण तरीके से इससे इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रों ने लाइब्रेरी के बाहरी हिस्से पर कब्जा जमा कर वहां तकड़ड़ी और टीन से झोपड़ियां बना ली और वहां बैठ गए, गाना गाने लगे, नारे लगाने लगे और भाषण देने लगे। उन्होंने नेल्सन मंडेला के चित्र लगाए, जो कि बीस साल से अधिक समय से जेल में थे और जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को रंगभेद विरोधी आंदोलन और संघर्ष को समर्पित कर दिया था। येल में बिताए ये कुछ महीने थे, जब मैं पहली बार भारत से बाहर था। हालांकि मैं उम्र के तीसरे दशक के अंतिम हिस्से में था, लेकिन मुझे इससे बहुत वास्ता नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए भारतीय प्रेस को दोष दे सकता हूं, जिसने तब उस देश पर शायद ही कभी कोई रिपोर्ट दी हो, शायद इसलिए कि वहां के नस्लवादी शासन के साथ हमारे कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। टूटू को टेलीविजन पर सुनने और उनके भाषणों की रीपेट्स पढ़ने और येल के अधिकशतया श्वेत छात्रों में उसका प्रभाव देखने के बाद देर से ही सही दक्षिण अफ्रीका में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। भारत लौटने के बाद मैं दक्षिण अफ्रीका की राजनीति का करीब से अनुसरण करने लगा। इस बीच, प्रतिबंधों को लेकर कदम उठाए जाने लगे। मारोटे थैचर और रोनाल्ड रीगन, जिन्होंने पहले नस्लवादी सत्ता की आलोचना करने के प्रति अविच्छेद दिखाई थी, कुछ आवाज उठाने लगे। नेल्सन मंडेला उस समय तक जेल में ही थे, लेकिन कुछ विदेशी आगंतुकों से मिलने की उन्हें इजाजत दी गई। उनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैलकम फेसर भी शामिल थे, जिनसे मंडेला का पहला सवाल था, क्या डॉन ब्रैडमैन अभी जिंदा हैं? 1991 में मैं लंदन में था और वहां गोपालकृष्ण गोखले के घर पर मेरी मुलाकात अर्रिज पादरी ट्रेवोर हड्डलस्टन से हुई थी, जिन्हें नस्लवाद की आलोचना करने की वजह से 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका से निष्कासित कर दिया गया था। जेहात्मबर्ण क्षेत्र का पादरी रहते हुए हड्डलस्टन ने कई उल्लेखनीय युवाओं को तराशा, जिनमें डेसमंड टूटू और जाज संगीतकार हग मस्केला शामिल थे। एक समय के तेजतर्रार प्रचारक तब उम्र के सातवें दशक के अंतिम वर्षों में पहुंच चुके थे और कुछ कमजोर लग रहे थे। डिन्न टैबिल पर वहां मौजूद जब एक अन्य मेहमान ने उनकी सेहत के बारे में पूछा तो हड्डलस्टन का जवाब था, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझसे पहले रंगभेद की मौत हो जाएगी। हड्डलस्टन की इच्छा पूरी हुई और 1994 में नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने के बाद वह थोड़े समय के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1997 और 2009 के दौरान मैंने खुद दक्षिण अफ्रीका की पांच बार यात्रा की। इन यात्राओं में मैंने रंगभेद विरोधी संघर्ष की कुछ उल्लेखनीय शख्थियतों से मुलाकात की। उनमें कवि मोंगेन वैली सेरेट, समाजशास्त्री फातिमा मीर, न्यायविद एल्बेड सैस और इतिहासकार रेमंड सूटनर शामिल थे। उन्होंने और उनके जैसे अन्य लोगों ने वीरतापूर्वक इतिहास के घावों को अपने पीछे छिपा लिया था, और अब वे एक पूर्ण और बहु-नस्लवीय लोकतंत्र के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से काम कर रहे थे। अफ्रीकी, भारतीय, रंगीन, श्वेत। वे एक इंद्रधनुष राष्ट्र (एक शब्द, संयोगवश, 'डेसमंड टूटू द्वारा गढ़ा गया) के अस्तित्व में आने का प्रतिनिधित्व करते थे। दक्षिण अफ्रीका की मेरी यात्रा के दौरान मैं कभी आर्कबिशप टूटू से नहीं मिल सका। हालांकि 2005 में टूटू जब एक निजी यात्रा पर बंगलुरु आए थे और तब मुझे भी उनके सम्मान में दिए गए एक डिन्नर में आमंत्रित किया गया था। मैं उनके साथ करीब बीस मिनट तक रहा। हमने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के बारे में बात की, जिनके दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क और रोमांचक स्ट्रोक प्ले की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। इसके बाद मैंने उन्हें ट्रेवोर हड्डलस्टन से हुई मेरी मुलाकात के बारे में बताया। इतना सुनते ही उन्होंने कहा, ट्रेवोर अफ्रीकियों जैसा हंसते थे, उनका पूरा शरीर हिलने लगता था। यदि उनके साथ मेरे कुछ व्यक्तित्व संबंध न भी होते, तब भी डेसमंड टूटू के निधन पर मैं उनना ही दुखी होता। क्योंकि वह अपने देश में और अन्य देशों में भी नैतिकता की मिसाल के तौर पर पहचाने जाने वाले शायद अंतिम जीवित व्य्क्ति थे। वह दक्षिण अफ्रीका की अंतरात्मा थे, जिन्होंने सीधे तौर पर रंगभेद शासन की नस्लीय ऋता का सामना किया, और खुले तौर पर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे रंगभेद के बाद के शासन के भ्रष्टाचार और वंशवाद की भी आलोचना की।

जब भी चुनाव आते हैं, नेताओं के सपने में भगवान आने लगते हैं, लेकिन हम जैसे आम मतदाताओं के ऐसे भाग्य कहां? हमें तो रात का देखा हुआ सपना दिन में भूल जाता है। जैसे हम

कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका को बिसार चुके हैं और तीसरी लहर के कहर से भी बेखोफ हैं। भूलना हमारी फितरत में है। बीती ताहि बिसार दे' के चलते ही हम अपने स्वर्णिम अतीत को भी भूल गए। इसीलिए हमको बार-बार हमारा इतिहास याद दिलाना पड़ता है। और तो और, हम वे लोग हैं, जो प्रत्याशियों द्वारा पिछले चुनाव में किए गए वादों तक को भूल जाया करते हैं। हमें सरकारों की उपलब्धियां याद नहीं रहतीं। जो अभूरा छूट गया है वह ही हमारी जेहन में नाचता रहता है। इस बार के इलेक्शन में चुनाव आयोग ने कोरोना-संक्रमण के भय से चुनाव-प्रचार में कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब चुनाव में दौड़-भाग न हो, भीड़ जुटाकर ऊंची-ऊंची न छोड़ी जाए तो उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं को बदहजमी होने लग जाती है। इसके चलते ही बहुत सारे नेता इन दिनों अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की ओर भागने लगे हैं। कुछ इधर से भागकर उधर जा रहे हैं। कुछ उधर से दौड़कर इधर आ रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप' का मेला लगा हुआ है। इस मेले की भीड़ में असली मुद्दे लोप' हैं। सभी पार्टियां कुछेक प्रत्याशियों के टिकट रिपीट कर रही हैं और कुछ के पते कट रहे हैं। जिनके कट रहे हैं, वे लोग अपने ही शीर्ष नेताओं को काट खाने को उतावले हो रहे हैं। ऐसे घमासान वातावरण में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, मुझे निस्संकोच बतलाओ! टिकट बंटवारे के इस दौर में उन भूतपूर्व प्रत्याशियों पर कैसी गुजर रही है, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। जो समरभूमि में निर्दलीय खड़े हो पाने की

अब चुनाव में दौड़-भाग न हो, भीड़ जुटाकर ऊंची-ऊंची न छोड़ी जाए तो उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं को बदहजमी होने लग जाती है। इसके चलते ही बहुत सारे नेता इन दिनों अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की ओर भागने लगे हैं। कुछ इधर से भागकर उधर जा रहे हैं। कुछ उधर से दौड़कर इधर आ रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप' का मेला लगा हुआ है। इस मेले की भीड़ में असली मुद्दे लोप' हैं। सभी पार्टियां कुछेक प्रत्याशियों के टिकट रिपीट कर रही हैं और कुछ के पते कट रहे हैं।

हिममत का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे हैं। हे संजय, मुझे उन महारथियों के बारे में भी जानने की उक्तट अभिलाषा है, जो अपने जुगाड़ बैठ पाने में असमर्थ हैं और आँधे मुंह लेटे हुए हैं, फिर भी एक बार और चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। और तो और, जिनकी पराजय सुनिश्चित है, वे तक अति आत्मविश्वास से सराबोर हैं। तुम अपनी खुली आंखों से और भी जो कुछ देख पा रहे हो, वह भी मुझे फटाफट बताओ।' संजय कहते हैं, सुनो राजन। चुनाव-क्षेत्र की कर्मभूमि में विजय की इच्छा वाले पराक्रमी प्रत्याशियों और उनके बाहुबली बलवान

तथा शूरवीर समर्थकों को देखकर मतदाता के अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। वोटर भ्रमित हैं। सभी दल लोकतंत्र की भजनावलियां गा रहे हैं। ऐसे में भीम्य और भीम तथा दुःशासन और जयदथ के बीच का अंतर तिरौहित है। इस चुनावी समरांगण में अब पक्ष-विपक्ष का कोई सिद्धांत शेष नहीं रह गया है। जिन्हें भी टिकट का अस्त्र नहीं मिल पाया है अथवा प्राप्त न हो पाने की आशंका है, वे एक पक्ष से उचककर दूसरे पक्ष के रथ पर बैठने को आतुर है।'धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, यह जो कुछ भी हो रहा है, इसे तुम ही देखो। यूं भी मेरा वोटर आइडि गलत बना हुआ है। उसमें मेरे नाम-पते के साथ किसी आंख वाले की फोटो चस्पा है। वैसे, मैं कम-से-कम इस चुनाव तक तो अंधा ही बना रहना चाहता हूं। इस नाते मैं अपना पहचान-पत्र दुरुस्त करने भी नहीं जाने वाला हूं।' संजय कहते हैं, हे अखंड राजन, मैं आपकी इस चिर अंधता को प्रणाम करता हूं। जिनकी दोनों आंखें सही-सलामत हैं, वे ही भला कौन-सा सही और गलत की पहचान कर पा रहे हैं? सत्य तो यह है कि जब चुनाव की राई उड़नी आरंभ हो जाती है, तब अधिकांश आंख वालों की आंखों में ही नहीं, उनकी अकल पर भी भ्रम का पर्दा पड़ जाया करता है।

सो हे राजन, आप सौभाग्यशाली हैं कि सत्य दिखलाने वाली ये आंखें आपके पास हैं ही नहीं। और यदि होतीं भी तो आप कर भी क्या लेते? आपके अपने दोनों कान अभी तक खुले हुए हैं, आप इसे ही गनीमत समझिए। कुछ दिनों बाद आप चुनावी शंखनाद के शोर और राजनीतिक पाटियों के नए-एए दावे और वादे सुनकर स्वयं ही अपने दोनों कानों में रूई टूस लेंगे।'

जाति मजहब के सहारे राजनीति करने और चुनाव के मौके पर पाला बदलने वालों को सबक सिखाएं मतदाता

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यह देखना निराशाजनक है कि चुनावी चर्चा में विकास और सुशासन की बातें कम और भावनात्मक मुद्दे अधिक हावी हो रहे हैं। यह अपने देश की विडंबना है कि जब भी चुनावों, खासकर विधानसभा चुनावों का दौर आता है तो विकास और जनकल्याण के वे बातें भी नजर नहीं आतीं, जो चंद दिनों पहले तक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में होती हैं। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 के पिछले चुनाव की अपनी चमत्कारिक सफलता दोहराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच साल के अपने कार्यकाल के दौरान विकास के कई ऐसे कार्य किए, जो पहले की सरकारों में सियासत की भेंट चढ़े हुए थे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का चुनाव ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों को जाति-मजहब की राजनीति करना अधिक फायदेमंद दिख रहा है। चूंकि भाजपा विपक्षी दलों की ध्रुवीकरण वाली राजनीति से अवगत है, इसलिए वह चुनावों की दिशा को अपने मूल मुद्दों यानी विकास और सुशासन के साथ हिंदू अस्मिता की ओर ले जा रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में जिस तरह भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ विकास का सिलसिला कायम हुआ और वाराणसी में काशी कारिडोर के रूप में एक असंभव सा कार्य किया गया, उसका स्वाभाविक लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी भाजपा के लिए बड़ा संबल है, जो स्पष्ट वक्ता के साथ एक सक्षम प्रशासक के रूप में उभरे हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों का समर्थन हासिल कर अपना जनाधार व्यापक किया है। उसने यह धारणा तोड़ी है कि वह केवल अगड़ों की पार्टी है। इसी कारण वह स्वामीप्रसाद मौर्य सत्य अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद अपनी जीत को लेकर उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुख्य रूप से अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा से मुख्य चुनौती मिलने जा रही है। अखिलेश ने रालोद के साथ अन्य छोटे दलों से गठबंधन किया है। अखिलेश चुनावी सफलता के लिए मुस्लिम-यादव के

अपने परंपरागत आधार पर टिके हुए हैं। सपा ने भाजपा का उड़ दिखकर ध्रुवीकरण करने वाली सियासत से न तो कभी परहेज किया और न उसे छिपाने की कोशिश की। जहां तक बसपा की बात है, उसके पास दलितों का एक आधार अवश्य है, लेकिन वह तब तक निर्णायक नहीं हो सकता, जब तक उसे अन्य जातियों का समर्थन न मिले। उत्तर प्रदेश में लगाभग समाप्त हो चुकी कांग्रेस में प्रियंका गांधी नई जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें संदेह है कि उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। पंजाब में भी राजनीतिक परिदृश्य भावनात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द सिमटा दिख रहा है। कांग्रेस ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन को हवा देने के साथ यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सिखों की पहचान पर संकट है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जो कांग्रेस मोदी सरकार सरीखे कृषि कानूनों की वकालत कर रही थी, वही सिख समुदाय को गुमराह करने के लिए उन कानूनों के विरोध में सबसे आगे आ गई। कांग्रेस ने सिखों के ध्रुवीकरण की कोशिश इसलिए भी की, क्योंकि वह नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के विवाद को सही तरह नहीं संभाल सकी। भाजपा पंजाब में कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन शायद ही कर सके, लेकिन वह फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोकने की घटना के जरिये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। वह इस प्रकरण का फायदा अन्य राज्यों में भी उठा सकती है। वैसे तो अकाली दल पंजाब में एक मजबूत विकल्प रहा है, लेकिन उसके वयोवृद्ध नेता प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक सक्रियता सीमित हो जाने और अन्य नेताओं का प्रभाव सिमट जाने के कारण वह भी भावनात्मक मुद्दों के सहारे अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू है आम आदमी पार्टी का उभार। कांग्रेस में आठ दूरार और अकाली दल के पतन होने का सबसे अधिक फायदा आप ही उठाती दिख रही है। आश्चर्य नहीं कि आप पंजाब में एक विकल्प के रूप में सामने आए। उत्तराखंड की चुनावी तस्वीर भाजपा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। उसके लिए इस सवाल का जवाब देना

कठिन है कि पांच साल में तीन मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन का रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए अवसर बन सकता है, लेकिन उसके केंद्रीय नेतृत्व की निष्क्रियता और दिशाहीनता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कमजोरी भाजपा की ताकत बन सकती है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह असंतोष जताया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनावों में ध्रुवीकरण और जातीय राजनीति को अस्वीकार करे तो राजनीतिक दल भी वास्तविक मुद्दों वाली राजनीति के लिए विवश होंगे। मुस्लिम समाज को इस पर चिंतन-मनन करना होगा कि उसे कब तक भावनात्मक मुद्दों तक सिमटाए रखा जाएगा? तीन तलाक जैसे सामाजिक सुधार के मुद्दे उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होने चाहिए। यही बात जाति के आधार पर वोट देने वालों पर लागू होती है। दलित-पिछड़े वर्ग के अनेक नेता सिर्फ इसलिए अपनी राजनीति चमकाने में सफल होते हैं, क्योंकि वे अपने समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं करें। जाति-मजहब के सहारे राजनीति करने और चुनाव के मौके पर पाला बदलने वाले नेताओं को मतदाता ही सही सबक सिखा सकते हैं। जाति-मजहब आधारित वोट बैंक की राजनीति के दुष्प्रक को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता अपने वोट की महत्ता समझें और सुशासन अथवा जनकल्याण की कसौटी पर किसी दल अथवा प्रत्याशी को अपना समर्थन दें।

मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए संज्ञान

पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा होते ही मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह लोक लुभावन वादे किए जाने लगे हैं, उन पर निर्वाचन आयोग को सज़ान लेना चाहिए। राजनीतिक दलों को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे आर्थिक नियमों की अनदेखी कर मनचाही घोषणाएं करें। एक समय था, जब लोक लुभावन घोषणाओं के तहत मुफ्त चीजें देने के वादे तमिलनाडु तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यही काम देश भर में होने लगा है। जब एक दल मुफ्त चीजें देने की घोषणा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने के लिए विवश होते हैं। इसके बाद उनमें एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग जाती है। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। गोवा, पंजाब, मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई दल मुफ्त बिजली देने के वादे कर रहा है तो कोई मोबाइल-लैपटॉप बांटने की बातें कर रहा है। चूंकि इन दिनों किसानों के मसले चर्चा में हैं इसलिए उनके कर्ज माफ करने की भी घोषणाएं की जा रही हैं। लोक लुभावन वादे करने की राजनीति किस तरह बेलगाम होती जा रही है, इसे इससे समझा जा सकता है कि अब नकद राशि देने के भी वादे किए जा रहे हैं। यह एक तरह से मतदाताओं के वोट खरीदने की कोशिश है। यहां इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चुनावों के दौरान गुपचुप रूप से पैसे और शराब बांटने का सिलसिला पहले से ही कायम है। यह एक तथ्य है कि चुनावों के दौरान उस पैसे की बड़े पैमाने पर ब्रामदगी होने लगी है, जो मतदाताओं के बीच चोरी-छिपे बांटने के लिए एकत्र किया जाता है। चुनावों के अवसर पर राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली अनाप-शनाप लोक लुभावन घोषणाओं का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने यह पाया था कि साड़ी, मिक्सी, मोबाइल, टीवी आदि मुफ्त देने की घोषणाओं से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद ही ध्वस्त हो जाती है। सच तो यह है कि ऐसी घोषणाएं अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का भी काम करती हैं। जब कोविड महामारी के चलते राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खस्ताहाल है तब फिर राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की रेवडियां बांटने की प्रवृति पर रोक लगाना और भी आवश्यक हो जाता है। बेहतर होगा कि निर्वाचन आयोग ऐसे कोई दिशानिर्देश जारी करे, जिससे राजनीतिक दलों की मनमानी घोषणाओं पर लगाम लगे। इस पर लगाम लगना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह समझ जाना चाहिए कि इस संस्कृति को बढ़ावा देकर कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता।

हिंदी साहित्य में दयनीय महानता और वैचारिक सन्नाटा दूर करने के लिए करना होगा ये काम

इन दिनों हिंदी साहित्य में एक अजीब किस्म का सन्नाटा दिखाई देता है। कुछ रचनाकार कई बार अपने लेखन से तो कई बार अपनी टिप्पणियों से इस सन्नाटे तो ठोड़ने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा नियमित तौर पर पेंसबुक पर कोई टिप्पणी लिखकर साहित्य के ठहरे पानी में कंकड़ फेंकती रहती हैं। कई बार उस पर विवाद भी होता है। बीच-बीच में लेखक संगठनों के नाम पर कुछ नए पुराने लेखक अपील आदि जारी करते रहते हैं लेकिन उसका भी कहीं कोई असर दिखाई नहीं देता है। ऐसी अधिकतर अपील किसी न किसी चुनाव के पहले ही जारी की जाती है। अब तो इसका असर इंटरनेट मीडिया पर भी नहीं होता। जमीनी स्तर पर तो शायद अपील पहुंचती भी नहीं है। कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में फासीवाद को लेकर चिंतित ही नहीं रहते हैं बल्कि उसके खतरों से लोगों को अगाह भी करते रहते हैं। उधर सरकार

के विभिन्न मंत्रालय और विभाग साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में वैचारिक विरोधियों को लगातार स्थान देती रहती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रिका आजकल के आवरण पर धुर वामपंथी कवि की तस्वीर छपती है। इसके पहले भी वामपंथी विचारधारा के लेखकों के चित्र आजकल पत्रिका के आवरण पर नियमित तौर पर छपते रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सरकार के घोषित विरोधियों को दिया जाता है। फिल्म फेस्टिवल से लेकर युवा महोत्सव तक में सरकार विरोधियों की फिल्में और वक्ता के तौर पर उनको आमंत्रित करके सरकार लगातार अपने लोकतांत्रिक होने का प्रमाण देने में जुटी है। बावजूद इसके विचारधारा विशेष के लेखकों को 2014 के कुछ से भी फासीवाद का डर सता रहा है। अब वामपंथियों में एक नई प्रवृति स्पष्ट दिखने लगी है। पहले वो अपनी विचारधारा से संबद्ध राजनीतिक दलों के लिए काम करते थे। पिछले

तीन चार साल से हो रहे चुनावों में वामपंथी दलों की हालत बहुत खराब हो गई है। अब अधिकतर वामपंथी लेखकों को कांग्रेस में संभावना नजर आने लगी। वामपंथी लेखक अब खुलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया पर उनके लिखे को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है। उनको अब इंदिरा गांधी के फासीवाद की बिस्कुल याद नहीं आती। उनको आपातकाल के दौर की ज्यादातियों की भी याद नहीं आती। निर्मल वर्मा ने तमिल लेखक पी कृष्णन से एक बातचीत में स्पष्ट रूप से इंदिरा गांधी की फासीवादी नीतियों और हिंदी के लेखकों पर अपनी राय रखी थी। निर्मल वर्मा ने कहा था, सबसे अधिक चौंकानेवाली बात थी इंदिरा गांधी की अलोकतांत्रिक तथा अत्याचारी नीतियों का बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जरा भी विरोध न किया जाना। वैसे तो इंदिरा गांधी की तानाशाही हल्की थी लेकिन इस हल्के संस्करण ने भी हमारे बुद्धिजीवी

वर्ग को खासा भयभीत कर दिया था और उन्होंने घुटने टेक दिए थे। इस ऋम में निर्मल ने रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती तक का नाम लिया था। निर्मल ने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था कि हिंदी के बड़े साहित्यकार इतने भंगुर और सारहीन सिद्ध होंगे। अब जब वामपंथी लेखक भय से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से इंदिरा गांधी की विरासत की प्रशंसा कर रहे हैं। संभव है इस वजह से प्रभाव नहीं पैदा कर पा रहे हैं। साहित्य के राजनीतिक दांवपेंच से अलग हटकर अगर कहा था कि उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था तो वर्तमान परिदृश्य बहुत आशाजनक नहीं लगता है। अब भी वरिष्ठ और बुजुर्ग साहित्यकार ही अपनी सक्रियता से रचनात्मक संसार को जीवंत बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। हिंदी के अधिकतर युवा लेखक आत्ममुपधता के शिकार हो गए हैं। छोटे-मोटे

उपन्यास लिखने वाले भी खुद को प्रेमचंद से बड़ा कथाकार मानने लगा है। उसकी अपेक्षा भी होती है कि साहित्य समाज उनको प्रेमचंद से अधिक सम्मान भी दे। इसी अहंकार में वो आलोचना से लेकर समीक्षा विधा को खारिज करने लगते हैं। इंटरनेट माध्यम पर होने वाली फूहड़ या प्रशंसात्मक चर्चा को सत्य मानकर वो अपनी कृति को महान समझ लेते हैं। कवियों के तो कहने ही क्या, वो तो खुद की रचनाओं पर मुग्ध रहते ही हैं। साहित्य के इस दौर को देखकर एक मित्र की टिप्पणी सटीक लगती है। उसने एक दिन कहा था कि हिंदी साहित्य में ये दयनीय महानता का दौर है। आज अगर हिंदी साहित्य में किसी प्रकार का कोई विमर्श नहीं हो रहा है तो उसके पीछे के कारणों की पहचान करनी होगी। राजेन्द्र यादव से हमारा वैचारिक स्तर पर काफी विरोध रहता था लेकिन उनकी इस बात के लिए उनके विरोधी भी प्रशंसा करते थे कि वो साहित्य में अद्भूते प्रश्न उठाते थे।

नामवर सिंह धुर वामपंथी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे लेकिन जब वो लिखते थे तो उससे साहित्य जागत में हलचल होती थी, उनके लिखे के पक्ष विपक्ष में बातें होती थीं। अशोक वाजपेयी भी जब तक वामपंथ की राजनीति में नहीं उलझे थे तब तक उनके लेखन में एक वैचारिक उष्मा होती थी। इनके बाद की पीढ़ी में भी देखें तो ज्ञानरंजन से लेकर रवीन्द्र कालिया तक के लेखन में कुछ ऐसे तत्व अवश्य होते थे जो पाठकों के बीच चर्चा की वजह बनते थे। नरेन्द्र कोहली के लेखन में लगातार प्रयोग होते थे जो पाठकों को नई तरह से सोचने का आधार देते थे। कमलकिशोर गोयनका ने प्रेमचंद को समझने की नई दृष्टि हिंदी साहित्य जागत को दी। इन लोगों में अहंकार नहीं था और वो अपने पूर्वज लेखकों को कभी खारिज नहीं करते थे। उनको साहित्य की परंपरा का भी ज्ञान था और उसपर वो गुमान भी करते थे।

कांग्रेस की पहली सूची: अपने गढ़ पटियाला में मौजूदा विधायकों पर ही दांव, घोटाले में फंसे धर्मसोत को भी टिकट

पटियाला । पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को पते खोल दिए। कांग्रेस के गढ़ माने जाते पटियाला में पार्टी ने कोई फेरबदल नहीं किया, बल्कि एक बार फिर से अपने मौजूदा विधायकों व मंत्रियों पर ही भरोसा दिखाते हुए उन्हें टिकट दिए हैं। छह में से चार सीटों पर मौजूदा विधायकों को उतारा, जबकि एक सीट पर मौजूदा विधायक व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बेटे को टिकट दे दिया। वहीं सन्नौर सीट से पिछले चुनावों में हारे प्रत्याशी व सिद्धू के करीबी हरिंदरपाल सिंह हैरीमान पर ही दोबारा भरोसा जताते टिकट दी गई है। पटियाला क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से छह पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का शनिवार को एलान कर दिया। इनमें पटियाला देहली सीट से इस बार



के पार्टी छोड़ने के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया था। धर्मसोत को कैप्टन का काफी करीबी भी माना जाता रहा है। इस कारण उनका इस बार टिकट मिलना काफी मुश्किल माना जा रहा था। उधर, सन्नौर सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से हरिंदरपाल

(शहरी) व शूतरणा सीटों को लेकर अभी भी कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के कारण पटियाला (शहरी) सीट के लिए कोई टक्कर का उम्मीदवार तलाशना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कभी कांग्रेस इस सीट से कैप्टन को हराने के लिए आप के पूर्व सांसद डा. धर्मवीर गांधी पर खेरे डालती है, तो कभी नवजोत सिंह सिद्धू को इस सीट से उतारने की चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। शूतरणा सीट के मौजूदा निर्मल सिंह को पार्टी दोबारा टिकट देने के मूड में नहीं लग रही है, क्योंकि निर्मल सिंह अपनी ही पार्टी के खिलाफ अकसर बगावती झंडा बुलंद करते दिखते हैं। पार्टी अब शूतरणा से किसी युवा चेहरे को उतारना चाहती है। वहीं पटियाला देहली से कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा

एक नजर

सिरसा पहुंचे डिप्टी सीएम का किसान नेताओं पर तंज: दुष्यंत ने कहा- पहले चुनाव लड़ लें, आंदोलन बाद की बात; पड़ोसी राज्यों के इलेक्शन बड़े दिलचस्प

सिरसा । हरियाणा के सिरसा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने के सवाल पर फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसान पहले चुनाव लड़ लें, आंदोलन बाद की बात है। उनका आंदोलन किसान हित में नहीं, बल्कि चुनाव के लिए था। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दुष्यंत चौटाला रविवार को डबवाली रोड स्थित सिरसा क्लब में पहुंचे। यहां उन्होंने क्लब में नव निर्मित द लाउंज भवन का उद्घाटन किया। कर्मचारियों के आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ लगते तीन राज्यों में दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं। जरूरत पड़ी तो वे चुनाव प्रचार के लिए तीनों राज्यों में जा सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा किसान आंदोलन के दौरान किसानों की संशा साफ हो चुकी थी कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की जगह संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि किसान आंदोलन राजनीति चमकाने के लिए था। चुनावी मैदान में उतरने से सह जगजाहिर हो गया है। उन्होंने प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू होने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरूआत की जा चुकी है। युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब भी कोई भी वैकेंसी होगी, उनमें 30 हजार से कम तनखाह वाली नौकरी में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

पानीपत में चोरों ने खाकी पर डाला डका : पुलिस प्रवक्ता अनिल की जेब से बस में चढ़ते वक्त पर्स चोरी किया, नकदी और जरूरी कागजात थे

पानीपत , हरियाणा के पानीपत शहर में बस अड्डा पर सक्रिय चोरों का गिरोह हर शख्स को अपना निशाना बना रहा है। अब इन चोरों के हौंसले इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्होंने खाकी को भी अपना निशाना बना डाला। चोरों ने पानीपत पुलिस प्रवक्ता सिपाही अनिल की जेब से बस में चढ़ने के दौरान पर्स चुरा लिया। चोरों ने पर्स अनिल की जींस की पिछली जेब से निकाला। सिपाही अनिल बस में पानीपत से अपने घर गोहाना जाने के लिए चढ़ा था। इस दौरान उसके साथ यह घटना घट गई। मामले को शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 379 के तहत केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई व चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में सिपाही अनिल ने बताया कि वह गोहाना का रहने वाला है। वह पानीपत एसपी कार्यालय में बतौर ब्रह्म कार्यपत है। 15 जनवरी की शाम करीब सवा 7 बजे वह अपने ऑफिस से घर जाने के लिए बस अड्डा पानीपत पहुंचा। वह रोडवेज बस नंबर ITM68B560 में चढ़ने लगा तो किसी चोर ने उसकी जींस की पिछली जेब से पर्स चुरा लिया। पर्स में विभाग का आई कार्ड, बैंक का डेबिट व फोर्ड्ट कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी सिम कार्ड व 2740 रुपए समेत अन्य जरूरी कागजात थे। सिपाही अनिल का कहना है कि जब वह पानीपत से बस में सवार होकर गोहाना जा रहा था तो रास्ते में डाहर टोल के पास उसने अपनी जेब चेक की। जेब में पर्स नहीं था। वह रविवार को फिर पानीपत आया और सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी।

पानीपत बिजली निगम कार्यालय में हुड़दंग : बिल न भरने पर कर्मियों ने उखाड़ा मीटर तो नाराज युवक सुआ लेकर पहुंचा, एलएएम से गाली-गलौज

पानीपत । हरियाणा के पानीपत जिले के गांव छाजपुर स्थित बिजली निगम कार्यालय में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक ने बिजली का बिल नहीं भरा था। जिसके चलते बिजली कर्मियों ने सुबक के बाहर लगा मीटर उखाड़ दिया था। इससे आहत युवक धारापर सुआ लेकर बिजली निगम के दफ्तर पहुंचा और कर्मचारियों पर हमला करने की नीयत से पीछे-पीछे दौड़ा। कर्मचारियों ने खिड़की दरवाजों से कुद कर खुद का बचाव किया। मामला कुछ शांत हो जाने पर निगम के एएसडीओ ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 323, 353, 427 व 506 के तहत केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में बिजली निगम के एसडीओ ने बताया कि बिजली निगम की टीम ने गांव छाजपुर काला निवासी रवि के मकान का बिजली बिल पोंडेंडा होने के कारण मीटर उतार लिया था। रवि को लाइनमैन स्टाफ ने कहा कि बिल भरने के बाद मीटर दोबारा से साइड में लगा दिया जाएगा। 14 जनवरी को रवि बिजली निगम कार्यालय में आया। वह A.L.M हरविन्द्र को कहने लगा कि तुने मेरा मीटर उतारा है, तू ही मेरे मकान की लोरो को डायरेक्ट पोल पर लगाएगा। A.L.M ने डायरेक्ट केबल लगाने से मना किया तो वह तैश में आ गया और गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इसके बाद वह हाथ में सुआ लेकर उसके पीछे दौड़ा। रूख्जान बचाने के लिए कार्यालय के अंदर घुसा और कम्प्रे का दरवाजा बंद कर लिया। रवि ने लेजर सेक्शन के कम्प्रे के दरवाजे पर सुए से हमला करके शीशा तोड़ दिया और अंदर जाने का प्रयास किया। कर्मचारी जान बचना के लिए खिड़कियों से कुदकर इधर-उधर भागने लगे। कार्यालय में अचान-तफरी का माहौल बन गया, जिस कारण काम बंद हो गया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि अगर उसकी केबल पोल पर डायरेक्ट नहीं लगाई तो वह जान से मार देगा।

हिसार सेंट्रल जेल से हवालाती दे रहा धमकी : इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट पर चाचा को परिवार समेत खत्म करने की पोस्ट डाली

हिसार । हरियाणा की हिसार सेंट्रल जेल में बंद एक हवालाती अपने ही परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है। अवैध मिस्ट्रल रखने के मामले में गिरफ्तार कारवाही निवासी अमित उर्फ मीता ने इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस अपडेट किया है। अमित उर्फ मीता की आईडी से अपडेट स्टेटस में उसने लिखा है कि जो करना है, कर लो परिवार वालों, उसके बाद मैं करूंगा, इशारा ही काफी है। आदमपुर पुलिस ने इस मामले में अमित के चाचा उमैद सिंह व नरेश कुमार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धमकी देने का केस दर्ज किया है। उमैद सिंह के अनुसार, अमित उनको कई बार पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका है और 6 दिन पहले ही अवैध मिस्ट्रल के साथ पकड़ा गया था। तब भी उसने कुबूल किया था कि वह अपने चाचा के परिवार को खत्म करने के लिए राजस्थान से मिस्ट्रल खरीदकर लाया था। उमैद सिंह के अनुसार, आरोपी अब सेंट्रल जेल हिसार में बंद है और उसकी सोशल मीडिया आईडी से लगातार उनको धमकी भरे मैसेज भेजे जा रहे हैं। पुलिस इसकी जांच करने में जुटी है कि इस आईडी को कौन, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है।

कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ा तो अगले पखवाड़े होगा पीक पर, गुरुग्राम व फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले

चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना अब विकराल रूप लेता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमण दर 18.36 प्रतिशत पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमण दर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले पखवाड़े में कोरोना पीक पर पहुंच जाएगा। मौतों का लगातार बढ़ता ग्राफ भी स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है। एक पखवाड़े में 33 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें से 20 मौतें पिछले पांच दिन में हुई हैं। हरियाणा में पिछलेहाल 416 हज़ार अवसीजन बेड और 149 मरीज आइसीयू और 44 लोग वेंटिलेटर पर हैं।शनिवार को 9050 नए संक्रमित मिले जिससे एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 46 हजार 720 पर पहुंच गई है। इनमें 40 हजार 95 लोग घरों में ही उपचारधीन हैं, जबकि छह हजार 625 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटों में 3743 रोगी ठीक होकर घर लौटे और सात की मौत हो गई। सोनीपत में दो और गुरुग्राम, यमुनानगर, अंबाला, भिवानी व फतेहबाद में एक-एक मरीज ने दम तोड़ दिया। 22 जिलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 3349, फरीदाबाद में 1764, करनाल में 389, सोनीपत में 403, अंबाला में 522, पंचकुला में 510, पानीपत में 271, हिसार में 262, रोहतक में 239, यमुनानगर में 199, झज्जर में 184, कुश्नगर में 172, भिवानी में 75, सिरसा में 148 व फतेहबाद में 53 संक्रमित मिले। सबसे कम पलवल में 17 और नूह में 34 नए रोगी मिले है। प्रेडेशन में ऑमक्रोन की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण का पैलवार तेजी से हो रहा है। पिछले तीन दिनों में ऑमिक्रोन का कोई नया मरीज नहीं मिला है। इसके उलट दैनिक संक्रमितों का आंकड़ा नौ हजार के पार पहुंच गया है।

फतेहाबाद में जंगली सुअर का शिकार : 4 बंदकें लेकर वन्य जीवों को मारने पहुंचे थे काजलहेड़ी, पुलिस ने किया 10 के खिलाफ केस दर्ज



फतेहाबाद । हरियाणा के फतेहाबाद के गांव काजलहेड़ी में जंगली सुअर के शिकार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार शिकारी 10 की संख्या में थे और बंदूकें लिए हुए थे। ग्रामीणों ने मोबाइल फोन से उनकी वीडियो भी बनाई। शिकार की सूचना के बाद वन्य प्राणी विभाग के गार्ड मौके पर पहुंचे और खानबीन की। फिलहाल बड़ोपल चौकी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर खानबीन शुरू कर दी है। वन्य प्राणी विभाग के निरीक्षक दलजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पास 15 जनवरी को ग्रामीणों का फोन आया कि गांव काजलहेड़ी में 10 से अधिक लोग बंदूकें लेकर आए हैं। वे सभी शिकार के लिए वन्य जीवों को ढूँढ रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि इनका शिकार किया जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। लेकिन उनकी गाड़ी को देख कर शिकारी मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर आदि ने पुलिस के साथ जांच की। वहीं पाया गया कि एक जंगली सुअर को गोली लगी हुई है। सुअर का पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। करीब 10 से अधिक लोग थे। उनके पास चार बंदूकें थीं। ऐसे में पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

125 करोड़ की ठगी : बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट के जीजा पर भी शिकंजा कसा, छापे में कई किलो चांदी और सोने के गहने बरामद



गुरुग्राम । राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) प्रशिक्षण केंद्र में टेंडर दिलाने के नाम पर 125 करोड़ की ठगी मामले में गुरुग्राम पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। एसआईटी की टीम शनिवार को मुख्य आरोपी बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव के जीजा आईटीबीपी में सहायक कमांडेंट नवीन खातोदिया के घर पहुंची और कई घंटों तक जांच-पड़ताल की। इस दौरान टीम को कई किलो चांदी और

भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद हुए।

इन सोने-चांदी के आभूषणों की कीमत का आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के जीजा के घर से एक लाख रुपये नकद, कई कीमती घड़ियां, तीन लैपटॉप और प्रवीण यादव की पत्नी ममता यादव का पासपोर्ट भी बरामद किया। बता दें कि आरोपी नवीन खातोदिया आईटीबीपी से एनएसजी में प्रतियुक्ति पर आए हैं और बीते

काफी समय से परिवार के साथ एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र में मिले मकान में रह रहे थे। आकलन करने में जुटी रही पुलिस : पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सहायक कमांडेंट नवीन खातोदिया के घर से ज्वेलरी की बरामदी होने के बाद पुलिस उसका आकलन करने में जुटी रही।

जांच के दौरान पुलिस के साथ एनएसजी के अधिकारी भी मौजूद रहे और वीडियोग्राफी भी की गई। पुलिस

काफी समय से परिवार के साथ एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र में मिले मकान में रह रहे थे। आकलन करने में जुटी रही पुलिस : पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सहायक कमांडेंट नवीन खातोदिया के घर से ज्वेलरी की बरामदी होने के बाद पुलिस उसका आकलन करने में जुटी रही।

जांच के दौरान पुलिस के साथ एनएसजी के अधिकारी भी मौजूद रहे और वीडियोग्राफी भी की गई। पुलिस

को ज्वेलरी में सोने और चांदी के सिक्के, अंगुठिया, चैन, कड़े सहित लज्जती और काफी महंगे सोने के सेट मिले। सारे सामान की लिस्ट बनाई गई और अपराध शाखा मानेसर की टीम द्वारा कब्जे में लिया गया।

लैपटॉप से खुलेंगे राज : मानेसर अपराध शाखा प्रभारी और मानेसर थाना प्रभारी के अनुसार तीन लैपटॉप की भी विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी। इससे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। तीनों लैपटॉप में पुलिस को पासवर्ड मिले हैं। रिमांड पर चल रहे आरोपियों से पासवर्ड के बारे में भी पूछताछ की।

पुलिस ने भेजा पत्र
आरोपियों द्वारा किए गए 125 करोड़ की ठगी के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ और आईटीबीपी में भी उनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा वहां से भी जानकारी जुटाई गई है। आरोपियों का व्यवहार कैसा था। हालांकि जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी छुट्टी पर चल रहे थे। इसके अलावा पुलिस ने तहसीलदार को भी पत्र लिखकर आरोपियों की संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीद की तारीख भी मांगी है, कब-कब खरीदी गई।

अंबाला में दहेज लोभियों ने घर से निकाला : लॉकडाउन में 5 लोगों की आई थी बरात, बुलेट देने पर पति नहीं हुआ खुश, पशुओं के बाड़े में सुलाया (वेब वार्ता)

अंबाला । हरियाणा के अंबाला जिले में कोरोना के चलते डेढ़ साल पहले लॉकडाउन में हुई शादी दहेज की भेंट चढ़ गई। जींद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो दहेज के लालची पति सहित परिवार के लोगों का हौंसला बढ़ गया। तरह-तरह की यातनाएं देते हुए विवाहिता को पशुओं के बाड़े में रहने को मजबूर कर दिया। पति को बुलेट के साथ 75 हजार रुपए दिए तो उसका मन नहीं भरा और पत्नी से मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया। अंबाला कैट के सुंदर नगर निवासी छाया ने अपने जौद निवासी पति सुरिंदर सिंह सहित ससुर सज्जन सिंह, सास शीला व जेट सुखबीर सिंह के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज करवाया। पड़ाव पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शिकायकर्ता छाया ने बताया कि शादी 1 मई 2020 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार, सुरिन्द पुत्र सज्जन सिंह से हुई थी। यह शादी लॉकडाउन के समय हुई थी। इस वजह से केवल 5 लोग ही बरात में आए थे। शादी में मां ने अपनी हँसियां से बद्धकर लगभग 3 लाख रुपया खर्च किया था। शादी के समय मां ने मेरे पति को



21,000 रुपए नकद, सोने की चैन व ब्रासलेट, एक सोने की अंगुठी तथा मेरी सास को सोने के कानों के टोपस, एक सोने की थोड़ी और एक पाजेब दी थी। एलसीडी 32 इंच सैमसंग आदि घरेलू सामान देकर विदा किया था। लेकिन ससुरालियों ने एक सप्ताह बाद ही तंग करना शुरू कर दिया था। छाया ने बताया कि ससुराल से कई बार 100 नंबर पर कॉल भी किया। लेकिन शिकायत पर जींद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 20 नवंबर 2020 को ससुराल दोबारा चली गई थी। मेरे पति ने मेरी सास, ससुर के पैर पकड़वा कर माफी मांगवाई, तब मुझे घर में आने दिया। मेरी सास ने मुझे अपने घर से बाहर थोड़ी दूर पशुओं के बाड़े में रहने के लिए मजबूर किया। मेरे भाई ने नई बुलेट मोटर साइकिल भी दी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

पंजाब में विद्रोह से घबराई कांग्रेस : अधिकतर पुराने चेहरों पर दांव, पहले 35 विधायकों के टिकट बदलने की थी चर्चा

जालंधर ।) पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार्दकमान घात लगाकर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह व भाजपा की टीम से काफी चक्करा गई और अधिकतर कई ऐसे पुराने चेहरों पर दांव खेल दिया, जिसकी टिकट काटने की पटकथा काफी समय पहले लिखी जा चुकी थी। कांग्रेस से बागी होकर नेता पार्टी छोड़कर भाजपा व कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस में जा सकते हैं, इससे हार्दकमान ने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाना उचित समझा। कांग्रेस ने चंद टिकटों में ही बदलाव किया है। जिसमें मालविका सूद और मानसा से सिद्धू सुसंवाला भी शामिल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के सीएम थे तो कांग्रेसी हार्दकमान रणनीति बना रही थी कि सत्ता विरोधी धार की कैसे



शामिल किया गया। फिर फतेहजंग बाजवा और हरदीप लाडी को। फतेहजंग बाजवा की टिकट कट रही थी। उसके भाई प्रताप बाजवा खुद मैदान में आ गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के कई विधायकों के संपर्क में भी थे। भाजपा में छह मंत्रियों

के जाने की चर्चा होने लगी। कांग्रेस को अपना किला ध्वस्त होते दिखाई देने लगा था। पार्टी के आला अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, टिकट नहीं कर रही थी। सबकी पीठ पर हाथ फेरा जा रहा था। मिशन साफ था कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान

था। इस कलह में कांग्रेसी दो फाड़ हो सकते थे और ऊपर से पार्टी के विधायकों को भाजपा व कैप्टन पहले ही लफ्कने के लिए खड़े थे।

मोगा से विधायक हरजोत कमल की टिकट काटकर मालविका सूद को दिया गया तो विश्वाकर्म कमल ने भाजपा में शामिल होकर आईना दिखा दिया कि अगर किसी विधायक की टिकट कटती तो निश्चित तौर पर सभी को लेने के लिए भाजपा व कैप्टन तैयार है। लिहाजा पार्टी ने अधिकतर पुराने चेहरों के नाम पर मोहर लगा दी है। भाजपा में बेशक कई दिग्गज शामिल हो रहे थे लेकिन पार्टी किसी भी चेहरे को टिकट देने की घोषणा नहीं कर रही थी। सबकी पीठ पर हाथ फेरा जा रहा था। मिशन साफ था कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान

श्रीमान निदेशक, सीबीआई से जांच की मांग पुल धोटाला केजरीवाल का सिचाई विभाग, सी.डी-2 बना भ्रष्टाचार का अड्डा

मुख्य अभियंता संजय सक्सेना, ई.ई सुधीर आर्या, अशोक कुमार, ए.ई, जुबैर खान ने ए-बी एक्स, ए-2 ब्लॉक, सुल्तानपुरी व मंगोलपुरी को जोड़ने वाले मुख्य पुल निर्माण में लगवाई बेहद घटिया निर्माण सामग्री, पुल में पड़ी दरारे व एक ओर से धंसा,



सुल्तानपुरी रोजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन

निगम में भाजपा की छवि को कालिक पोत रहे है भ्रष्ट अभियंता करोल बाग जोन, भवन विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा!

अवैध निर्माण की काली कमाई से अभियंता से उपायुक्त तक बने “अडानी”

उ.दि.न.नि के मुख्य सतर्कता अधिकारी मंगेश कश्यप बने मूक दर्शक कब तक चलता रहेगा भ्रष्टाचार का खेल



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग जोन में बिल्डर माफिया का राज सारे वार्ड बनते जा रहे है स्लम युक्त हर वार्ड में चार से पांच मंजिला, बेसमेन्ट सहित अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है।
अभियंताओं की काली कमाई चल-अचल व बेनामी सम्पत्ति की श्रीमान निदेशक जी, सीबीआई, भारत सरकार से जांच की मांग।

अध्यक्ष: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा